

नव भारत

पर्यटक बोले... एमपी के गांवों में है असली जीवन

रूरल टूरिज्म ने प्रदेश को दी नई पहचान, 1 साल में 57 फीसद बढ़ी पर्यटकों की दस्तक, ग्रामीण पर्यटन में एमपी नौवें पायदान पर

■ कहीं फिल्मों की शूटिंग तो कहीं जनजातीय जीवन बना पर्यटन का नया अनुभव

नवभारत टीम

भोपाल, 4 अक्टूबर. प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन ने उड़ान भरना शुरू कर दी है. अब देश के शीर्ष प्रदेशों में शुमार है. सितारा होटलों को हिल्स स्टेशनों से इतर गांवों में पर्यटकों रुख इसे हवा दे रहा है. देशी-विदेशी पर्यटकों के साथ ये टूरिस्ट स्पॉट रुपहले पर्वत की भी पसंद के रूप में उभर रहे हैं. इसकी वजह ग्रामीण परिवेश, शहरी चमक-दमक से दूर... चिड़ियों से सुबह की शुरुआत, चूल्हे पर पका भोजन, शुद्ध हवा और आत्मीय अतिथि सत्कार है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में विकसित हो रहे होमस्टे स्थानीय परिवारों को पर्यटकों से सीधे जोड़ रहे हैं. पर्यटक जहां गांव में कुछ दिन सुकून तलाशने पहुंच रहा है, वहीं गांव में उसके आने से रोजगार और आय की नई गतिविधियों की राह भी खुल रही है. छिंदवाड़ा का सावरवाणी, इंदौर बड़खेड़ा, सीधी का बकवा, ग्वालियर का अट्टर मॉडल टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित हो चुके हैं.



नवभारत

सरोकार

छिंदवाड़ा

सावरवाणी में पहले पर्यटक आए... अब फिल्मों के कैमरे भी

होमस्टे से ग्रामीणों को आय, युवाओं को काम और महिलाओं को मेहमाननवाजी से रोजगार

छिंदवाड़ा. सतपुड़ा की गोद में बसा सावरवाणी अपनी हरियाली और ग्रामीण परिवेश के कारण पर्यटकों को खींचता था. अब यही खूबसूरती फिल्म निर्माताओं की भी आकर्षित कर रही है. हाल ही में बंगाल से आई टीम ने यहां बंगाली फिल्म 'रायसेन रहस्य' की करीब एक सप्ताह शूटिंग की. नवंबर और दिसंबर में दो हिंदी फिल्मों की शूटिंग प्रस्तावित है. यह बदलाव अचानक नहीं आया. पर्यटन विभाग ने सावरवाणी को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया और 14 जनवरी 2014 से यहां होमस्टे की शुरुआत हुई. अब तक देश के कई राज्यों के साथ फ्रांस, यू.एई, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके से पर्यटक यहां आ चुके हैं.

अब तक ग्रामीण पर्यटन पर इस तरह से हो चुका काम

मध्यप्रदेश में वर्तमान में संचालित होम-स्टे

666

2026-27 में नए पंजीकृत होमस्टे

277

अकेले जबलपुर में होमस्टे

100

होमस्टे सीधी के बकवा में किए जाएंगे विकसित

10

15 लाख सालाना राजस्व जबलपुर से

57%

2025 में पर्यटक बढ़े

गोवा, हिमाचल को पीछे छोड़

मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश और गोवा की तुलना में अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करता है, भारत के हृदय में प्रतिदिन 500 विदेशी और 3.82 लाख घरेलू पर्यटक आते हैं. अब देश के पर्यटन मानचित्र को नया रूप दे रहा है. 2025 के नए आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य ने गोवा और हिमाचल प्रदेश जैसे पारंपरिक पसंदीदा पर्यटन स्थलों को पीछे छोड़ दिया है, जहां घरेलू पर्यटकों की संख्या में गिरावट देखी गई है.

वर्ष 2025 में वर्ष 2024 की तुलना में बढ़ी पर्यटकों की संख्या

7,64,32,229

2025 में मध्य प्रदेश पहुंचे कुल पर्यटक

21.05 करोड़

ग्वालियर : टूरिस्ट विलेज मॉडल अब अट्टर, मितावली और पढ़ावली तक पहुंच रहा



ग्वालियर-चंबल अंचल को पर्यटन के बड़े सर्किट से जोड़ने की कवायद के बीच गांवों को टूरिस्ट विलेज के रूप में विकसित करने की योजना तेजी से आकार ले रही है. दिल्ली-आगरा-औरंगा पर्यटन सर्किट के बीच स्थित ग्वालियर की ऐतिहासिक धरोहरों के साथ अब पर्यटकों को ग्रामीण जीवन, स्थानीय संस्कृति और देसी खान-पान का अनुभव कराने पर जोर है. शिवपुरी में करीब एक दशक पहले शुरू हुआ टूरिस्ट विलेज मॉडल अब अट्टर, मितावली और पढ़ावली तक पहुंच रहा है. मुर्ना के ऐतिहासिक मितावली-पढ़ावली गांवों को रिसॉर्ट्सबल टूरिज्म मिशन के तहत ग्रामीण पर्यटन परियोजना में शामिल किया गया है. बताया जा रहा है कि इन स्थानों में देसी बाजरे की रोटी, दाल-रोटी, मालपुआ और खीर जैसे पारंपरिक व्यंजन भी इस अनुभव का हिस्सा बनाए जा रहे हैं.

होमस्टे के जरिए पर्यटकों को मध्य प्रदेश के गांव, खान-पान और स्थानीय संस्कृति से सीधे जुड़ने का अवसर मिल रहा है. जबलपुर में इसकी संभावनाएं काफी व्यापक हैं. होमस्टे बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्थानीय आय के नए स्रोत तैयार हो रहे हैं.

-शरद दीक्षित, अध्यक्ष, होमस्टे वेलफेयर सोसायटी, मध्य प्रदेश

होमस्टे के माध्यम से पर्यटकों को स्थानीय परिवेश और ग्रामीण जीवन का प्रामाणिक अनुभव उपलब्ध कराया जा रहा है. जबलपुर में इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है. पर्यटन विभाग का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़ें और ग्रामीण पर्यटन का दायरा भी बढ़े.

-नवीन शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश विभाग, जबलपुर

प्रदेश में अब तक 418 ग्रामीण होमस्टे स्थापित किए जा चुके हैं. इन होमस्टे में 34 हजार से अधिक पर्यटक, जिनमें विदेशी मेहमान भी शामिल हैं, ग्रामीण जीवन, स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक आतिथ्य का अनुभव कर चुके हैं. इस पहल से ग्रामीण परिवारों ने 7.33 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त आय अर्जित की है. ग्रामीण होमस्टे योजना न केवल पर्यटकों को प्रदेश के ग्रामीण जीवन से जोड़ रही है, बल्कि ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रही है.

-डॉ. इलेयाराजा टी., प्रबंध संचालक, एमपी टूरिज्म बोर्ड



एक अड़चन दूर हो तो पंख लगे पर्यटन को : यहां भगोरा-कालाकुंड मार्ग का करीब तीन किमी कच्चा घाट सेवशन पर्यटन विस्तार के रास्ते में चुनौती है. सड़क की सुविधा बेहतर होने पर इस क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही और बढ़ने की संभावना है.

9 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को 36 करोड़ बोनस

46 हजार किलो ड्रग्स जब्त, फिर भी नहीं टूटी नशे की सप्लाई चेन

- ▶ सीएम ने 74 विकास कार्यों का किया भूमिपूजन
- ▶ वन समितियों को 26 करोड़ का लकड़ी लाभांश भी मिला

नवभारत न्यूज
मंडला, 4 अक्टूबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को मंडला में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 9 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों के खातों में 36.17 करोड़ रुपए की बोनस राशि अंतरित की. इस दौरान मंडला के साथ जबलपुर, डिंडौरी, बालाघाट और सिवनी जिलों के संग्राहक भी लाभान्वित हुए. मुख्यमंत्री ने 84 वन समितियों को 26.56 करोड़ रुपए का लकड़ी लाभांश भी वितरित किया. इसके अलावा जिले में करीब 460 करोड़ रुपए

की लागत के 74 विकास कार्यों को सौंपा जा रहा है. नक्सलवाद खत्म होने का किया दावा : मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मंडला, डिंडौरी और बालाघाट जैसे क्षेत्रों से नक्सलवाद खत्म हुआ है. उन्होंने प्रदेश के बजट में हुई वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में राज्य का बजट 4 लाख 38 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो गया है. मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उस समय अधिकारियों और कर्मचारियों को तबादलों के नाम पर डराया-धमकाया जाता था. कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके और सांसद फगन सिंह कुलस्ते सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. तेंदूपत्ता बोनस और लकड़ी लाभांश के

47 कार्यों का भूमिपूजन 27 का लोकार्पण

सिद्ध टेकरी, बड़ी खेरी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 263 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 47 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया. वहीं 197 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरे हुए 27 कार्यों का लोकार्पण किया. इन परियोजनाओं से जिले में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है. वितरण को वन समितियों तथा संग्राहकों को आय से जोड़कर देखा जा रहा है. वहीं विकास कार्यों के भूमिपूजन और लोकार्पण के जरिए जिले में बुनियादी सुविधाओं तथा निर्माण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया.

46 हजार किलो ड्रग्स जब्त, फिर भी नहीं टूटी नशे की सप्लाई चेन

विशेष प्रतिनिधि
भोपाल, 4 अक्टूबर. मध्यप्रदेश को वर्ष 2029 तक ड्रग्स और नशे के कारोबार से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियां तत्पर हैं. इस पहल से ग्रामीण परिवारों ने 7.33 करोड़ से अधिक की अतिरिक्त आय अर्जित की है. ग्रामीण होमस्टे योजना न केवल पर्यटकों को प्रदेश के ग्रामीण जीवन से जोड़ रही है, बल्कि ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रही है.

अब जिलेवार तैयार होगी ड्रग्स की कुंडली

नई रणनीति के तहत जिलों में सक्रिय बड़े तस्करों और उनके नेटवर्क की जानकारी जुटाई जाएगी. सफाया, पैसा लगाने वाले, नशे को रखने की जगह और उसे पहुंचाने वालों की अलग-अलग पहचान की जाएगी. इस के हॉटस्पॉट और स्कूल-कॉलेजों के आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों की भी पहचान की जाएगी. इसके अलावा तस्करों की अवैध संपत्ति की जांच, प्रमुख तस्करों रास्तों पर निगरानी और राज्य पुलिस तथा केंद्रीय एजेंसियों के बीच सूचनाओं का तेजी से आदान-प्रदान करने पर भी जोर दिया जा रहा है. कि पुलिस और जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन चुनौती सिर्फ छोटे तस्करों या नशे की खेप पहुंचाने वालों तक सीमित नहीं है. बड़े तस्कर पूरे नेटवर्क को चलाते हैं. इसमें नशे को व्यवस्था करने से लेकर उसे छिपाने, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, बेचने और पैसों का इंतजाम करने वाले लोग शामिल होते हैं. भोपाल के बागरोदा में सामने आई करीब 1,814 करोड़ रुपए कीमत की एमडी ड्रग्स फैक्ट्री ने भी इस नेटवर्क को गहराई सामने लाई. एनसीबी की चार्जशीट के अनुसार शोएब लाला को मामले का मुख्य आरोपी और हरीश आंजना को उसका प्रमुख सहयोगी बताया गया है.

पूर्व भाजपा नेता के बेटे के घर से शराब जब्त

दतिया, 4 अक्टूबर. अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन पुलिस ने उनाव रोड स्थित बस बाड़ी के पास एक मकान से करीब 59 लीटर देशी और अंग्रेजी शराब बरामद की है. पुलिस ने मौके से दो आरोपियों मुकेश साहू और सक्षम चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया, जबकि राकेश साहू फरार हो गया.

गुस्ताखी माफ

शराब मुक्ति से हो अभियान की शुरुआत : उमा भारती

नवभारत न्यूज
भोपाल, 4 अक्टूबर. मध्यप्रदेश को नशामुक्त बनाने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबमुक्ति की लड़ाई में शराबमुक्ति को लेकर अपनी पुरानी मांग फिर उठाई है. उन्होंने कहा है कि नशामुक्ति अभियान का पहला चरण शराब मुक्ति होना चाहिए. उमा भारती ने रविवार को सोशल मीडिया पर जारी संदेश में प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लक्ष्य को नशीले पदार्थों से मुक्त करने और कहा कि शराब मुक्ति को अभियान की शुरुआत का पहला कदम बनाया जाए. उमा भारती के मुताबिक शराब की लत लगने के बाद व्यक्ति दूसरे नशीले पदार्थों की ओर बढ़ सकता है. इसलिए मध्यप्रदेश को नशामुक्त बनाने की पहल में पहले शराब से मुक्ति पर ध्यान दिया जाना चाहिए. उन्होंने

नशामुक्त ऐलान पर पूर्व बीजेपी नेता ने की मांग
कहा कि मध्यप्रदेश को नशामुक्ति का केंद्र बनाने का असर पूरे देश पर पड़ेगा. दरअसल, अमित शाह ने 3 अक्टूबर को भोपाल में मध्यप्रदेश को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था. उन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर 2029 से पहले प्रदेश को नशीले पदार्थों से मुक्त करने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर योजना तैयार करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस लक्ष्य को लेकर योजना बनाने की बात भी कही गई थी. उमा भारती लंबे समय से मध्यप्रदेश में शराबबंदी की मांग करती रही हैं.

सौगात केंद्र सरकार की मदद से एमपी के 8 पिछड़े जिलों की बदलेगी तस्वीर

61 ड्राइविंग स्कूल, फिटनेस सेंटर खुलेंगे

भोपाल, 4 अक्टूबर. राज्य के पिछड़े जिलों में ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल, स्कैपिंग सेंटर और वाहन फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे. इन केंद्रों की स्थापना में भारत सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा.

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भारत सरकार ने देश में 120 आकांक्षी जिलों की पहचान की है. ये ऐसे जिले हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के ऐसे जिलों में ड्राइविंग प्रशिक्षण, स्कैपिंग और वाहन फिटनेस सेंटर खोलने के लिए राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना,

आठ आकांक्षी जिलों की पहचान

देशभर के 120 जिलों में से मध्य प्रदेश के आठ जिले—छतरपुर, दमोह, बड़वानी, राजगढ़, विदिशा, गुना, सिंगरौली और खंडवा—को स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, बुनियादी ढांचे और वित्तीय समावेशन जैसे सामाजिक-आर्थिक मानकों में पिछड़ने के कारण तेजी से विकास (कायाकल्प) के लिए चिन्हित किया गया है. सरकार पुराने बसों को स्कैप करने के लिए प्रोत्साहन भी देगी. राज्य में आठ स्कैपिंग सेंटर संचालित हैं; 21 और की जरूरत है. राज्य में 30 परीक्षण केंद्र संचालित हैं; छह और बनाने की जरूरत है. 29 ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों को मंजूरी दी गई है और 61 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल प्रस्तावित हैं.

सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से पुराने व प्रदूषण फैलाने वाले स्कैप करना है.